

मेट्रोपॉलिटन सिटी • आज से तीन दिन आईआईटी, आईआईएम के प्रोफेसर करेंगे मंथन, प्रमुख बिंदु शासन को भेजेंगे मांडू के महल जैसे 'सिटी रिचार्ज प्लेस' बनाएं, एकमुश्त जमा होगा पानी

भास्कर संवाददाता | इंदौर

यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के बीच देश के प्रमुख शहरों को बेहतर बनाने के लिए हुए समझौते के तहत जारी पांच दिनी कार्यशाला के दूसरे दिन मंगलवार को आईआईटी के प्रोफेसर व उनकी टीम ने आपदा और पानी के प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन दिया। अगले तीन दिन आईआईटी, आईआईएम के प्रोफेसर, आईडीए, टीएंडसीपी के अफसर, अर्बन प्लानर की टीम इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के

लिए विचार मंथन करेगी। 14 अक्टूबर को इन बैठकों का जो सार निकलेगा, वह शासन को भेजा जाएगा। मास्टर प्लान में भी इसका समावेश किया जाएगा। टेक्निकल सेशन में आईडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार, नगर निगम की एडिशनल कमिशनर भव्या मित्तल, चीफ इंजीनियर महेश शर्मा, टीएंडसीपी के सहायक संचालक केएस गवली, सारंग गुप्ता भी उपस्थित रहे। आयोजन की नोडल एजेंसी आईडीए है। आईआईटी के प्रोफेसर मुकेश गोयल व उनकी टीम ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी एकदम से नहीं बनाई जा

सकती है। इसके लिए अभी से प्रयास करना होंगे, तब जाकर आने वाले वर्षों में महानगर बन पाएगा। उन्होंने कहा कि महानगरों में भूजल, पेयजल बड़ी समस्या है। हमारे यहां हर घर वाटर रिचार्ज अनिवार्य किया गया है। यह अच्छी पहल है, लेकिन इसके स्थान पर शहर में बड़े स्थान चुने जाना चाहिए, जहां बल्क में बारिश का पानी जमीन में उतर सके। मांडू का महल उदाहरण है। पानी कितना भी गिरे लेकिन वह जाता एक ही दिशा में है। मेट्रोपॉलिटन सिटी से पहले रिसोर्स के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए।

महानगर में शामिल होने वाले उपनगरों में भी बेहतर स्टॉर्म लाइनें डाली जाएं

महानगरों में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अग्निकांड होने पर दिक्कत आती है। बारिश का पानी कई दिन तक उतरता नहीं है। दो-तीन इंच बारिश में ही जल जमाव हो जाता है। इन सब परेशानियों का निराकरण हमें पहले करना होगा। बेहतर स्टॉर्म वाटर लाइन न केवल सिटी बल्कि उन उपनगरों में भी होना चाहिए, जिन्हें मेट्रोपॉलिटन में शामिल किया जाना है।